

लाघु सिंचाई →

भारतीय किसान मौसम और वर्षा पर निर्भर रहा करते थे। समय पर वर्षा नहीं होने से खेती और फसल प्रभावित होती थी। अतः लाघु सिंचाई के लिए भूगर्भ जल चरियोजनाओं को लागू किया गया जिसमें पम्प-सेट, ट्यूब वेल आदि का गया।

उर्वरकों का प्रयोग →

भारतीय धरत ज्ञानि में उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया। देश में रासायनिक खाद का वृद्धि के लिए नए कारखाने लगाए गए आयात को नीति अपनायी गयी तथा पुराने कारखानों का विस्तार किया गया।

कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारण →

कृषकों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह एक आवश्यक कदम था। कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए आवश्यक था कि सरकार द्वारा मूल्यों को संरक्षण प्राप्त हो और वे गिरने नहीं पाएँ। यह कार्य कृषि मूल्य आयोग को सौंपा गया। सरकार द्वारा खरीद एवं विक्री मूल्य नियंत्रित होने के

फलस्वरूप कृषकों को काफी राहत मिली।
विभिन्न निगमों की स्थापना →

आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह एक आवश्यक कदम था।
कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए आवश्यक था कि सरकार →

ऊँचा कृषि को बढ़ावा →

सुविधाओं के अभाव में कृषकों को काफी परेशानी होती तथा आर्थिक विषमताओं को झेलना भी पड़ता। अतः कृषकों को काफी परेशानी होती तथा आर्थिक विषमताओं को झेलना भी पड़ता। अतः कृषकों को ऊँचा तथा सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिया गया।
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम →

में व्याप्त निर्धनता से ग्रामीण क्षेत्रों हमारे देश में ऐसी योजनाओं की आवश्यकता अनुभव की गयी जिनसे बेरोजगारी दूर हो सके। सन् 1977 में प्रस्तुत योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 48% तथा नगरीय क्षेत्रों में 41% लोग गरीबी में हैं।